

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर

प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ

डीजी परिपत्र संख्या- 71 /2016

दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 28, 2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या-17171(एम/बी)/2016 इकरार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनोंक 24-11-2016 पारित करते हुए यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि 156(3) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में मा० न्यायालय द्वारा अभियोग पंजीकृत किये जाने के आदेश पारित किये जाने के बाद अन्यत्त विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जा रही है और विवेचना भी अनावश्यक रूप से लम्बित रखी जाती है।

2- उल्लेखनीय है कि विवेचना में विलम्ब से साक्ष्य को नष्ट/विलोपित किये जाने की प्रबल सम्भावना रहती है जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आप सभी को समय-समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने एवं विवेचना में विलम्ब न किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश निर्गत किये गये हैं, इसके उपरोक्त भी इस प्रकार के दृष्टिकोण से आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मा० न्यायालय एवं इस मुख्यालय से निर्गत निर्देशों को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है जो कदाचित् उचित् नहीं है।

3- अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि 156(3) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर मा० न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर विवेचना शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित करायी जाय। भविष्य में यदि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति होती है तो अधोहस्ताक्षरी को आपके विरुद्ध भी कार्यवाही कराने हेतु विवश होना पड़ेगा।

(जावेद अहमद)
 पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर मा० न्यायालयों द्वारा 156(3) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों की नियमित समीक्षा कर उपरोक्त निर्देशों का कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित करायें:-

- 1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।